

प्रेषक,

श्री एस0एन0पी0एन0सिन्हा,  
आयुक्त एवं तयिव ।

सेवा में,

सभी समाहत्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 28.6.95

विषय- तैरात बंदोबस्ती संबंधी प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति हेतु समय पर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 2503 भू0सु0दिनांक 21 नवम्बर, 1974 तथा परिपत्र सं0 486रा0दिनांक 15.2.78 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा सरकारी निदेशा संसूचित किया गया था कि तैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव, जिनकी बंदोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है, बंदोबस्ती अवधि के शुरु होने के दो माह पूर्व निश्चित रूप से पेश जाय" । उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया था कि किसी संबंधित पदाधिकारी के स्तर पर ऐसे प्रस्तावों को अग्रसारित करने में विलम्ब हो तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय" । इन सब अनुदेशों के बावजूद पाया जा रहा है कि तैरात बंदोबस्ती के प्रस्तावों को भेजने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है । कुछ प्रस्ताव बंदोबस्ती अवधि के समाप्त होने पर तथा कुछ प्रस्ताव बंदोबस्ती अवधि के काफी समय बीत जाने के बाद भी प्राप्त होते हैं । ऐसी हालत में इन सब प्रस्तावों पर सरकार के समक्ष इसका कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था को मान लें । साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की वसूली भी संबंधित बंदोबस्तीदार से नहीं हो पाती जिससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक पत्राचार के साथ साथ गैर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है ।

सरकार चाहती है कि तैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव जिसकी बंदोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है, बंदोबस्ती अवधि के शुरु होने के दो माह पूर्व सरकार को भेजना सुनिश्चित किया जाय तथा किसी प्रकार का विलम्ब न हो । विलम्ब होने पर दोषी पदाधिकारी पर शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

